

यौन अपराध मामलों में न्याय के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट

प्रलिस के लिये:

[फास्ट ट्रैक कोर्ट](#), यौन अपराध मामलों में न्याय, [बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण](#) (POCSO) अधिनियम, 2012, [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#), [बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1992](#)

मेन्स के लिये:

यौन अपराध मामलों में न्याय के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

कानून और वधि मंत्रालय के न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत [फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट](#) का प्रदर्शन सहाहनीय रहा है, जिससे [बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण](#) (Protection of Children from Sexual Offenses- POCSO) अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेज़ी लाने में काफी प्रगति हुई है।

पृष्ठभूमि:

परिचय:

- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु समर्पित न्यायालय हैं। त्वरित सुनवाई होने के कारण नियमित न्यायालयों की तुलना में इनकी मामला नपिटान दर/कलीयरेंस दर बेहतर है।
- "आगामी पाँच वर्षों में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को खतम अथवा काफी सीमा तक कम करने के लिये" पहली बार वर्ष 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs) की सफिरशि की गई थी।
- दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के बाद केंद्र सरकार ने 'नरिभया फंड' की स्थापना की, [कशोर न्याय अधिनियम में संशोधन](#) किया तथा [फास्ट-ट्रैक महिला न्यायालयों](#) की स्थापना की।
 - इसके बाद कुछ अन्य राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार आदि ने भी बलात्कार के मामलों के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिये योजना:

- सरकार ने वर्ष 2019 में [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) के तहत लंबित बलात्कार के मामलों और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र नपिटान के लिये देश भर में 1,023 FTSCs स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की।
- यह यौन अपराधियों के लिये नविरक रूपरेखा को भी सशक्त करता है।

प्रदर्शन:

- FTSCs ने जून 2023 तक बलात्कार और POCSO अधिनियम से संबंधित 1.74 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक नपिटान किया है।
 - यह यौन अपराध के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु इन विशेष अदालतों के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।
- वर्तमान में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 763 FTSCs कार्यरत हैं।
 - इनमें से 412 वशिष्ट POCSO न्यायालय हैं।

POCSO अधिनियम:

■ परचिय:

- POC SO अधनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जसि बाल अधकियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1992 के भारत के अनुसमर्शन के परिणामस्वरूप अधनियमति कथिा गया था ।
- इस वशिष कानून का उद्देश्य बच्चों का यौन शोषण और उन यौन शोषण के अपराधों को संबोधति करना है, जनिहें या तो स्पष्ट रूप से परिभाषति नहीं कथिा गया या जनिके लयि पर्याप्त दंड का प्रावधान नहीं कथिा गया था ।
- यह अधनियम 18 वर्ष से कम आयु के कसिी भी व्यक्तिको बच्चे के रूप में परिभाषति करता है । अधनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है ।

■ वशिषताएँ:

- **लगि-तटस्थ प्रकृति:** यह अधनियम मानता है कलिङकथिाँ और लङके दोनों यौन शोषण के शकियार हो सकते हैं तथा पीड़ति के लगि की परवाह कथिा बनिा ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है ।
 - यह इस सदिधांत के अनुरूप है कसिभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा प्राप्तिका अधिकार है और कानूनों को लगि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहयि ।
- **मामलों की रपिर्ट करने में सुवधि:** अब न केवल व्यक्तथिाँ बल्कसिंस्थानों में भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रपिर्ट करने के लयि पर्याप्त सामान्य जागरूकता है कथिाँ रपिर्टगि न करने को POC SO अधनियम के तहत एक वशिषिट अपराध बना दथिा गया है ।
 - इससे बच्चों के खलिाफ अपराधों को छपिाना तुलनात्मक रूप से कठनि हो गया है ।
- **शर्तों की स्पष्ट परिभाषा:** बाल पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बना दथिा गया है ।
 - इसके अलावा 'यौन उत्पीड़न' के अपराध को **भारतीय दंड संहतिा** में 'महलिा की लज्जा भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के वपिरीत स्पष्ट शब्दों में (बढ़ी हुई न्यूनतम सज़ा के साथ) परिभाषति कथिा गया है ।

महलिा एवं बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लयि पहल:

- [बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [कशिोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियम, 2015](#)
- [बाल वविाह नषिध अधनियम \(2006\)](#)
- [बाल शर्म नषिध एवं वनियमन अधनियम, 2016](#)

UPSC सवलिा सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजयि तथा इसके कार्यान्वयन की स्थतिा पर प्रकाश डालयि । (2016)

प्रश्न. हमें देश में महलिाओं के प्रतियौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं । इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है । इस संकट से निपटने के लयि कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये । (2014)